भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 10

जिसका उत्तर दिनांक 02.02.2023 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में घरेलू और विदेशी निवेश

10 डा. फौजिया खान :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में घरेलू निवेश पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में प्राप्त घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वर्ष-वार राशि कितनी है;

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में देशों से प्राप्त सहायता में पर्याप्त वृद्धि या कमी हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) तथा (ख) एनपीसीआईएल की नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश का वित्तपोषण ऋण व सामान्य शेयर 70:30 के अनुपात में किया जा रहा है। सामान्य शेयर का वित्तपोषण एनपीसीआईएल के आंतरिक स्रोतों एवं सरकारी बजट की सहायता से किया जाता है।

(ग) वर्तमान एफडीआई नीति (सरकार की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति) परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है। इस प्रकार, एनपीसीआईएल द्वारा कोई एफडीआई प्राप्त नहीं की गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान एनपीसीआईएल में किए गए पूंजीगत निवेश (रुपये करोड़ में) का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत निवेश (रूपए करोड़ में)	7880.64	11813.00	10041.19	10052.02	14234.73

(घ) भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ ने कुडनकुलम, तमिलनाडु में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अंतर-सरकारी समझौता (आईजीए) किया है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं (केकेएनपीपी) 3 व 4 के साथ-साथ कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं (केकेएनपीपी) 5 व 6 का निर्माण कार्य आरम्भ होने से रूसी परिसंघ से प्राप्त साख में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ङ) भारत सरकार ने घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन किया है जिससे नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संयुक्त उद्यम सक्षम हो सके।

* * * * *